

# DAILY CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

02 APRIL 2025

THE HINDU

The Indian EXPRESS

HT Hindustan Times

UPSC (IAS/PCS) AND ALL  
COMPETITIVE EXAM

दैनिक जागरण

जनसत्ता



ABHAY SIR



# Events in News



## Topic 1

सरिस्का टाइगर रिजर्व और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

## Topic 2

"भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)"

## Topic 3

नवजातों के लिए वरदान साबित हुआ स्वच्छ  
भारत अभियान

## Topic 4

जल विद्युत परियोजनाएं और प्राकृतिक आपदाएं

# सरिस्का टाइगर रिजर्व और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

SARISKA TIGER RESERVE



- चर्चा में क्यों :- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राजस्थान सरकार को आदेश दिया गया था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास इसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी भी खदानें हैं उन्हें बंद कराया जाए।
- सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 68 खदानें हैं इन सभी को बंद करने का निर्णय दिया गया है।



## क्यों की जानी है ये सभी बंद :-

1. इन खदानों से अवैध खनन के कार्य किया जाता है
  2. अवैध खनन के कारण इस महत्वपूर्ण बाघ आवास में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि वह चाहता है की जितनी भी अवैध गतिविधियां होती हैं इन्हें बंद किया जाए जिससे बाघों के इस प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जा सके।
  - सुप्रीम कोर्ट 1990 के दशक से इस संदर्भ में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय दे चुका है।
  - इस क्षेत्र में अवैध खनन 1990 से ही एक बड़ी समस्या रही है



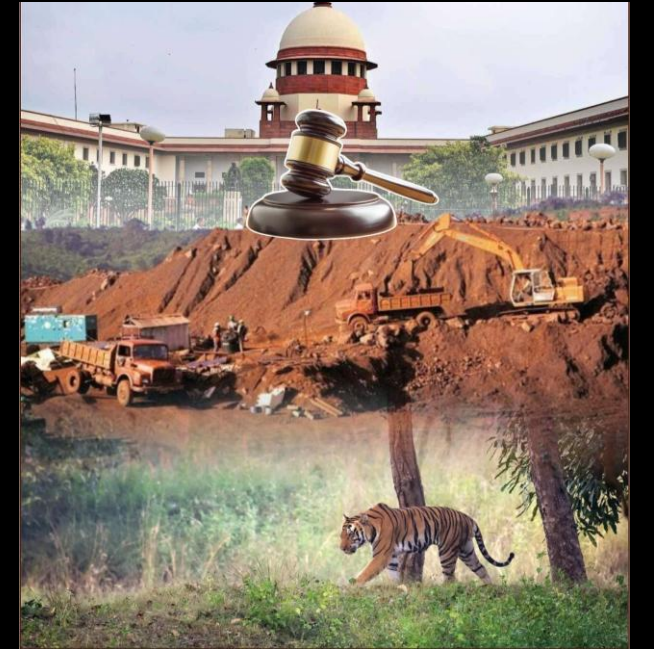
- सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह जो निर्णय दिया गया है इस निर्णय में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के को ध्यान में रखा।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दोनों ही अधिनियम स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्यों के पास उत्खनन की अनुमति नहीं होगी।



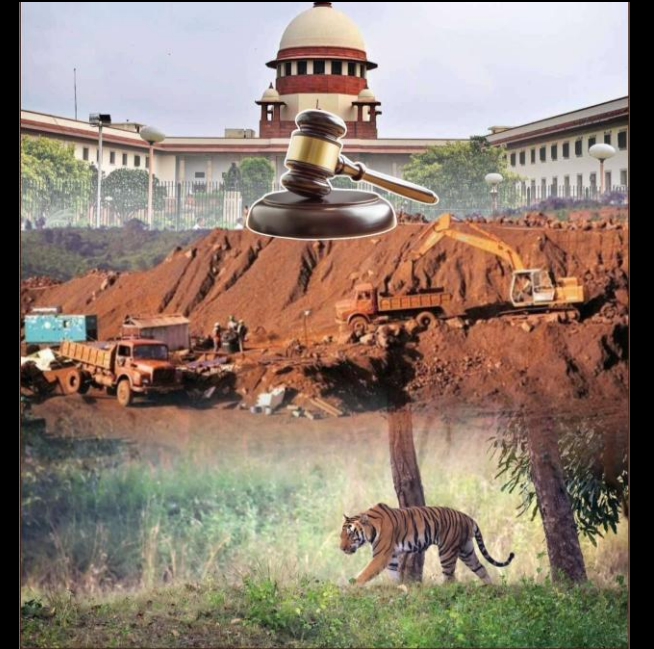
### **सरिस्का टाइगर रिजर्व एवम ऐतिहासिक संदर्भ और न्यायिक हस्तक्षेप :-**

- सरिस्का में खनन के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सबसे पहले अक्टूबर 1991 में एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के द्वारा पीआईएल के माध्यम से लाया गया।

- पीआईएल पर तुरंत अंतरिम आदेश के माध्यम से रिजर्व में खनन कार्य को रोक दिया गया
- साथ ही न्यायमूर्ति एम.एल. जैन ने सर्व कमेटी का गठन किया। और आदेश दिया कि 800 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है जिसका संरक्षण करना जरूरी है।
- सरिस्का के संदर्भ में न्यायालय का अगला महत्वपूर्ण आदेश अप्रैल 1993 में आया जिसमें अदालत ने इस क्षेत्र की 262 खदानों को बंद करने का आदेश दिया।
- 2000 के दशक के केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में बताया गया कि अभी भी इस क्षेत्र में अवैध खनन का उल्लंघन हो रहा था।

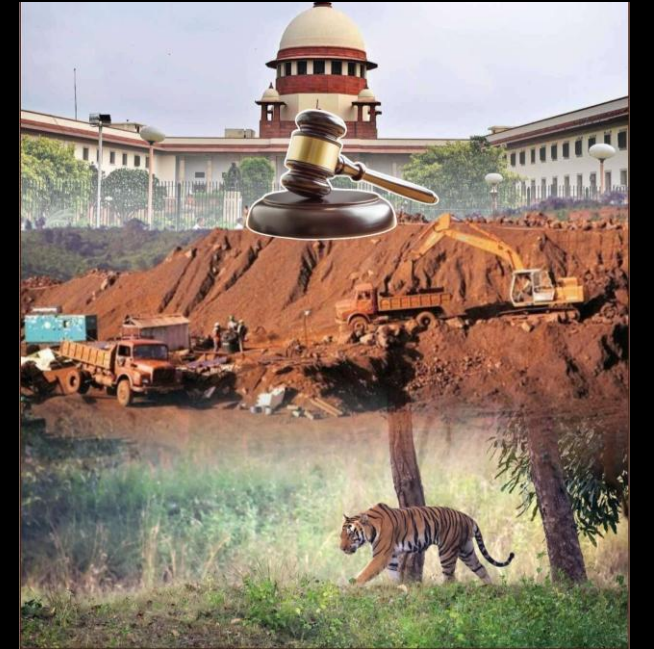


- जिस कारण न्यायालय ने और अधिक कठोर आदेश दिए जिसमें रिजर्व के चारों ओर 1 किलोमीटर का सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कहा।
- 2020 आते-आते जब स्थिति और गंभीर हुई और निरंतर चुनौतियों से परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट ने और शरत रख अपनाया
- 2014 में सरिस्का रिजर्व के जमुआ रामगढ़ के आसपास का एक किलोमीटर का क्षेत्र सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया जिसके अंदर किसी भी प्रकार के खनन को रोकने के अपने द्वारा 2006 में दिए निर्णय की पुष्टि की।





- 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में कुछ रियायत दी लेकिन इस क्षेत्र को नो मीनिंग जोन घोषित कर दिया।
- परंतु वर्तमान में भी इस क्षेत्र में अवैध प्रकार से खनन का कार्य जारी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए इस क्षेत्र के एक किलोमीटर के अंतर्गत 68 स्थान को चिन्हित किया है जिन पर जल्द से जल्द रोक लगाई जानी है



## सरिस्का टाइगर रिज़र्व:

- यह टाइगर रिज़र्व राजस्थान के अलवर ज़िले का एक भाग है यह अरावली पहाड़ियों में स्थित है और । इसे 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था
- बाघ अभयारण्य 1978 में घोषित किया गया। 1978 के बाद से ही यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना।

## इस रिज़र्व का एक इतिहास भी है

- इस रिज़र्व में कंकरवाड़ी नामक किला स्थित है जन श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि मुगल बादशाह है औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाई तारा से को पराजित कर इसी किले में कैद करके रखा था।

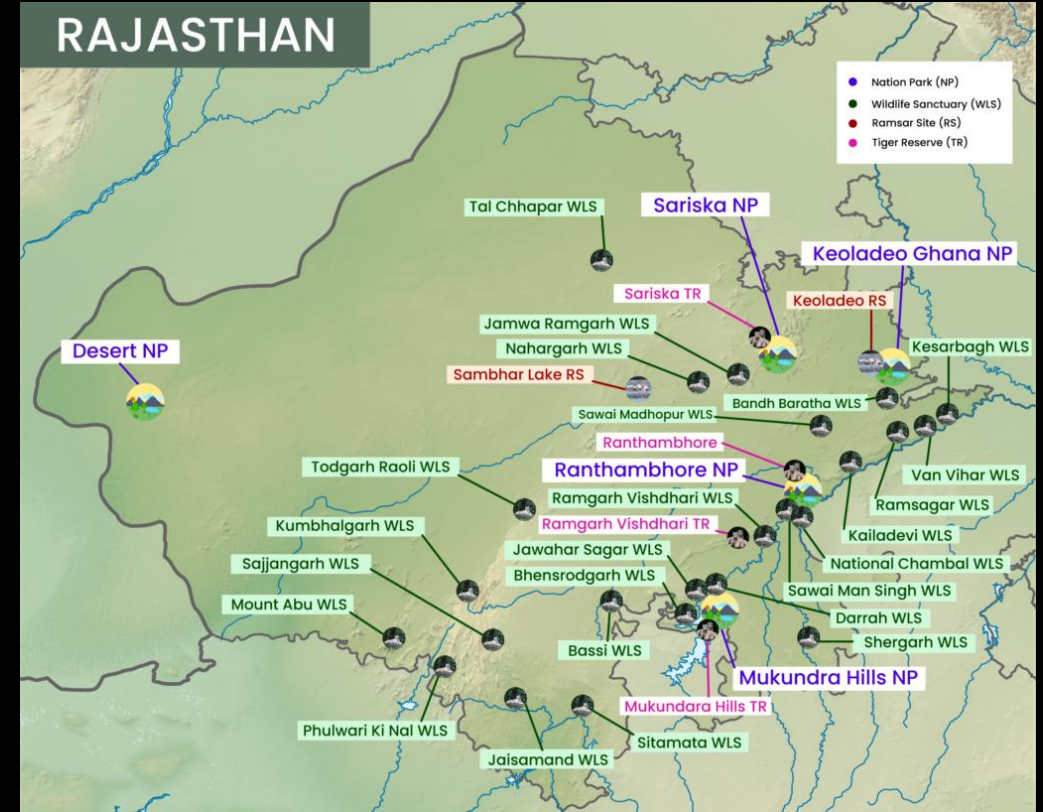


## मुख्य जीव:

- सांभर, चीतल, रॉयल बंगाल टाइगर तेंदुए, नीलगाय, आदि।

## राजस्थान के अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर
- सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर
- डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर
- रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जंक्शन पर)।



## निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. बाघ गणना (Tiger Census) हर साल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है।
- 2. भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
- 3. NTCA टाइगर रिजर्व को तीन जोन में विभाजित करता है - कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन।

## सही विकल्प चुनें:

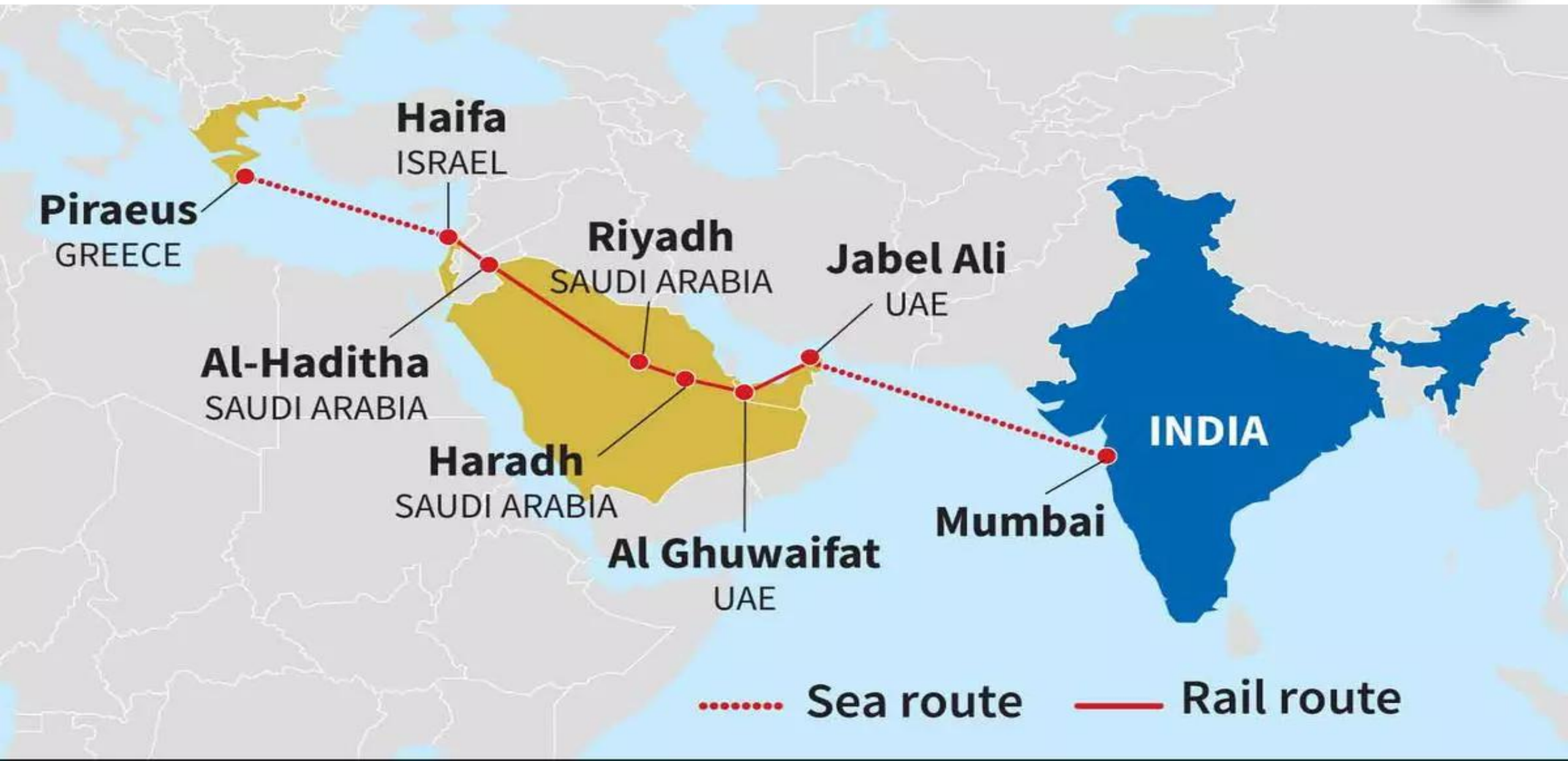
- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



## **व्याख्या:**

- बाघ गणना (Tiger Census) हर 4 साल में आयोजित की जाती है, हर साल नहीं।
- 2018 की गणना के अनुसार, भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
- टाइगर रिजर्व को कोर ज़ोन, बफर ज़ोन और ट्रांजिशन ज़ोन में विभाजित किया जाता है।

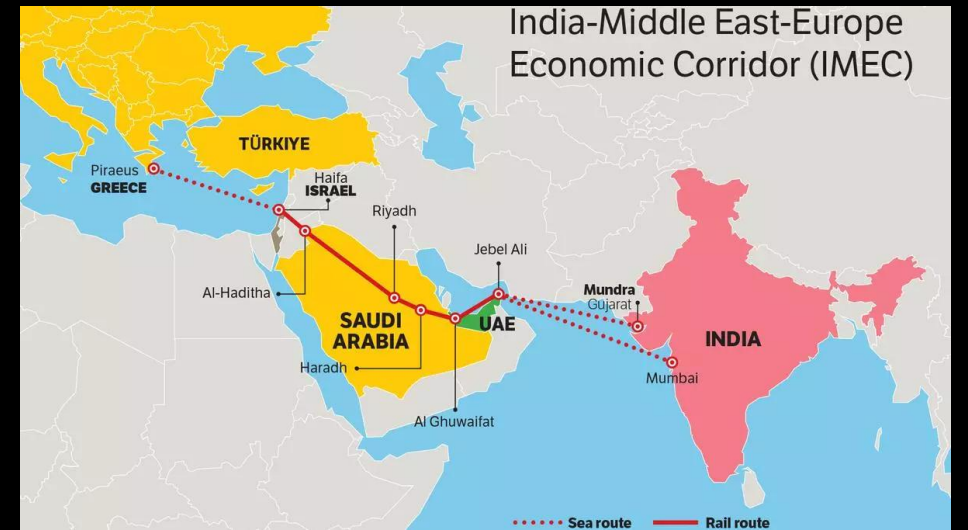
# "भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)"



- चर्चा में क्यों :- हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मध्य "भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)" चर्चा हुई।

### भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के बारे में

- आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है
- और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।



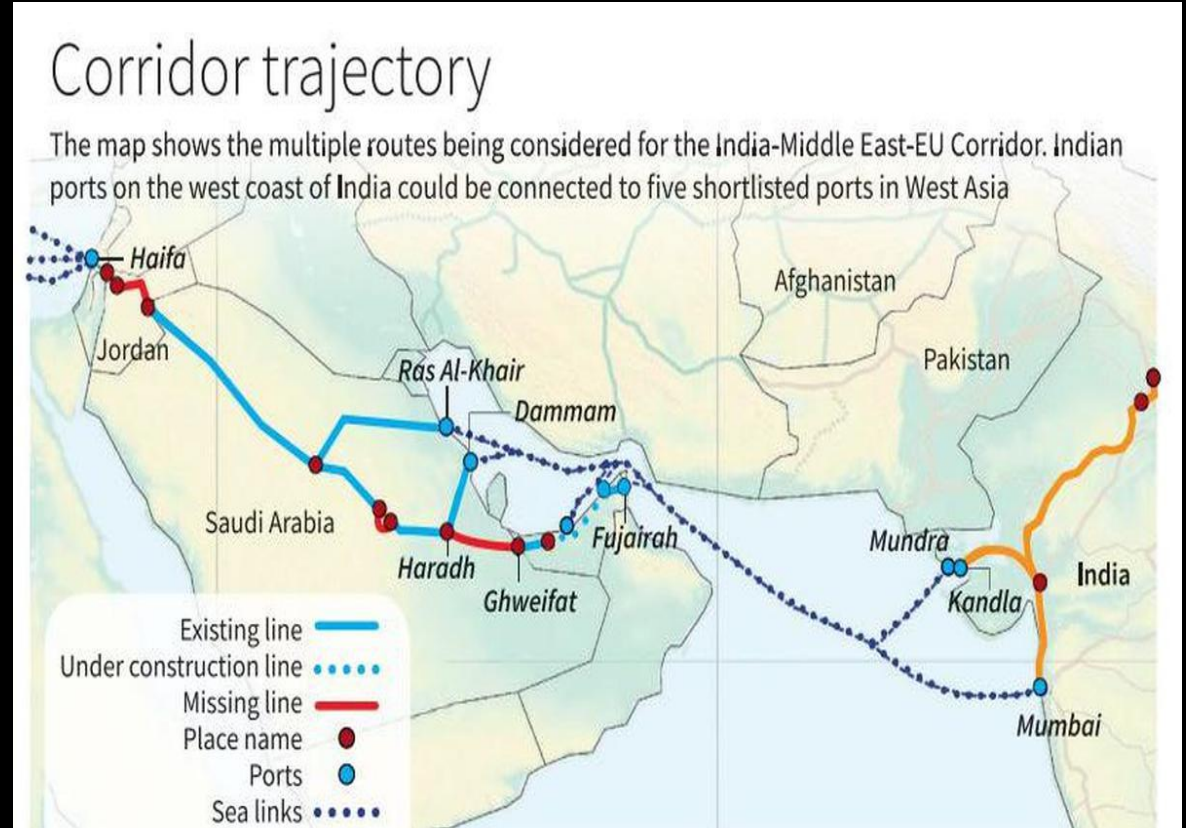
- यह IMEC गलियारे में समुद्री मार्गों के साथ ही रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे।
- साथ ही एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल प्रोग्राम को भी सामिल किया गया है।
- **IMEC गलियारे के लक्ष्य :-** एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ना है।
- इस योजना की स्थापना G20 शिखर सम्मेलन (2023) जिसका आयोजन भारत में किया गया था उसी समय भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था।





## IMEC गलियारे में जोड़े जाने वाले बंदरगाह:-

- भारत: – कांडला (गुजरात), मुंद्रा (गुजरात), और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई)।
- मध्य पूर्व में : संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा, ज़ेबेल अली और अबू धाबी के साथ ही सऊदी अरब में दम्मम तथा रास अल खैर बंदरगाह।
- रेलवे लाइन के माध्यम से फुजैरा बंदरगाह (UAE) को सऊदी अरब (घुवाईफात और हयाद) तथा जॉर्डन के माध्यम से हाइफा बंदरगाह (इज़राइल) से जोड़ा जाएगा।

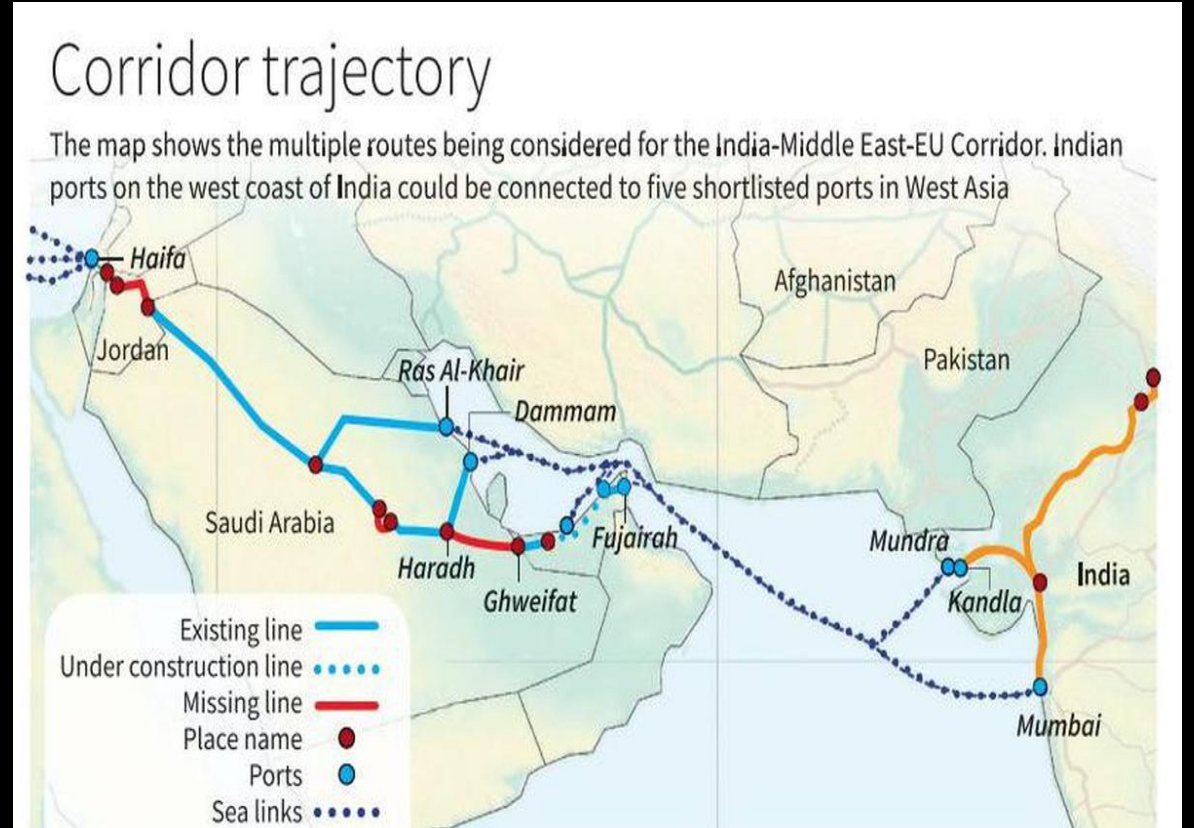


## इज़राइल: हाइफा बंदरगाह

- यूरोप: ग्रीस में पीरियस बंदरगाह, दक्षिण इटली में मेसिना और फ्रांस में मार्सिले

## IMEC गलियारे का महत्व :-

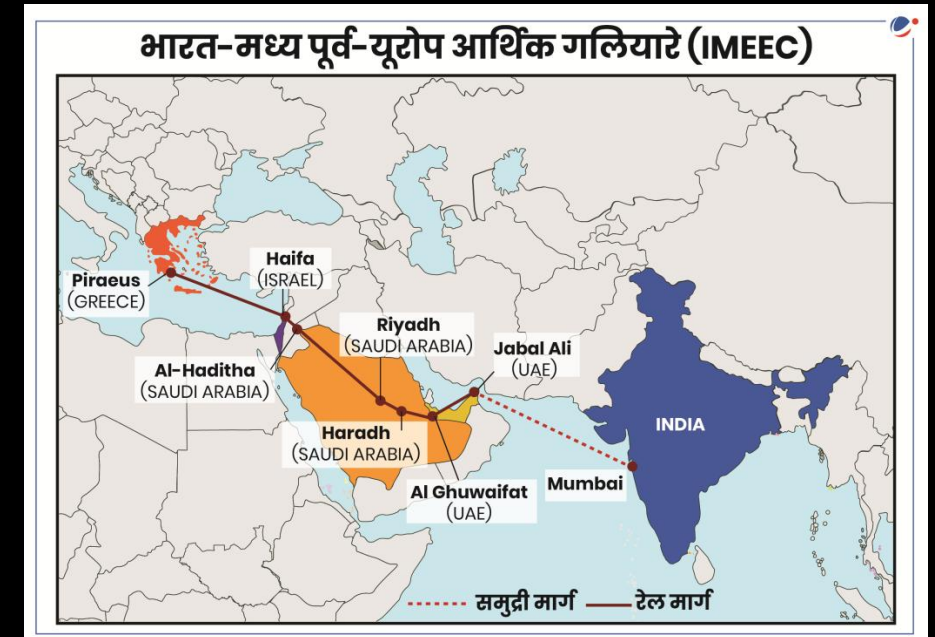
- यह गलियारा चीन की "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" (BRI) का एक विकल्प उपलब्ध करा सकता है।
- सभी सदस्य राष्ट्रों तथा अन्य राष्ट्रों के मध्य ऊर्जा और डिजिटल संचार को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा।



- पश्चिमी देशों के बाहर नई शक्तियों के उभरने का मौका मिलेगा
- भारत को अरब देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का मौका मिलेगा।
- भारत , मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाने का मौका मिलेगा।

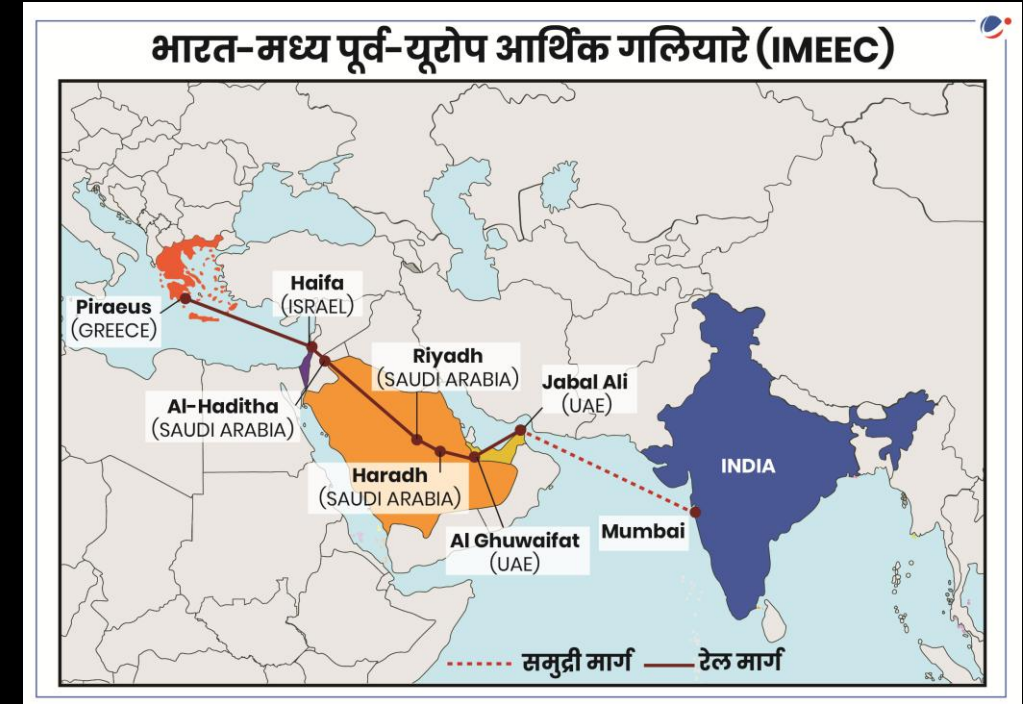
### IMEC से जुड़ी चुनौतियां :-

- इसराइल इस गलियारे का महत्वपूर्ण भाग है परंतु मध्य एशिया के कई देशों के साथ उसके संबंध अच्छे ना होने के कारण इस गलियारे के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है



## जैसे की :-

- इसराइल और सऊदी अरब के मध्य कूटनीतिक संबंधों में अधिक तीव्रता ना होना।
- इजरायल-हमास-ईरान संघर्ष ।
- परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधानों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है।



**भारत में आर्थिक गलियारों (Economic Corridors) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

- 1. आर्थिक गलियारे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए विकसित किए जाते हैं।
- 2. भारत में आर्थिक गलियारे केवल भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किए जाते हैं।
- 3. भारत सरकार की भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारों के विकास से संबंधित है।

**उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1 और 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3



## व्याख्या:

- आर्थिक गलियारे का उद्देश्य औद्योगिक विकास, व्यापार, और बुनियादी ढांचे में सुधार करना होता है।
- यह सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों सहित विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा विकसित किए जाते हैं, न कि केवल भारतीय रेलवे द्वारा।
- भारतमाला परियोजना भारत में आर्थिक गलियारों के निर्माण को गति देने के लिए बनाई गई है।

नवजातों के लिए वरदान साबित हुआ स्वच्छ भारत अभियान



# स्वच्छ भारत अभियान पर भाषण



“एक कदम स्वच्छता की ओर”

- भारत में स्वच्छता को लेकर किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में पता चला है कि “स्वच्छ भारत मिशन” के द्वारा बनाए गए शौचालयों के कारण हर साल 60 से 70 हजार नवजात बच्चों की मृत्यु होने से बचाया जा रहा है

### किसने किया सर्वे :-

- 1. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट
- 2. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया
- 3. द ऑहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़ी शोधकर्ता सुमन चक्रवर्ती, सोयरा गुने, टिम ए बुकनर, जूली स्ट्रोमिंगर और पार्वती सिंह द्वारा ।





- शोधकर्ताओं ने अध्ययन में भारत के पिछले दस वर्षों (2011-2020) के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के डाटा को लिया ।
- इस सर्वे के लिए आंकड़े 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके साथ 2000 से 2020 के बीच पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं और बच्चों की मृत्युदर में आए कमी के बीच के संबंधों की जांच की ।



## अध्ययन के नतीजे :-

- 1. जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में औसतन 10 फीसदी के सुधार जिससे शिशु मृत्यु दर में 0.9 अंकों की कमी।
- 2. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 1.1 अंकों की गिरावट आई है।

## बच्चों की मौत :-

- एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में सालाना पांच वर्ष से कम आयु के 54 लाख बच्चों को असमय अपनी जान गंवानी पड़ती है। इनमें से 20 फीसदी मौतें भारत में सामने आती हैं।



**प्रश्न. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2019)**

- A. अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे।
- B. ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।
- C. इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये सटीक और विस्तृत मानदंड उपबंधित हैं।
- D. अपशिष्ट उत्पादक के लिये यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़िले में उत्पादित अपशिष्ट, किसी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए।



# जल विद्युत परियोजनाएं और प्राकृतिक आपदाएं

Result Mitra



- चर्चा में क्यों :- हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं देखी गईं पर इन सब की विशेषता यह थी कि उनकी उपस्थित जल विद्युत परियोजनाओं के आसपास थी
- हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में ही 6 स्थानों पर बाढ़ फटने की घटना हुई। जो की प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत घटी एक घटना है।
- ये प्राकृतिक आपदाओं की अधिकतर घटनाएं किसी न किसी जल विद्युत परियोजना स्थल के आस-पास घट रही हैं।



## इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण :-

- विकास की अंधी दौड़ :- हम बिना पर्यावरण की चिंता किए अपने लाभ के लिए बड़े पैमाने पर इसे हानि पहुंचा रहे हैं।
- हम बिना पर्यावरण की देखें बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं जिससे बड़ी मात्रा में इसे हानि हो रही है।
- हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं।
- पिछले 7 दिन में ही 6 अलग-अलग स्थान पर बाढ़ फटने की घटना घटित हुई।



- हाल ही में घटित किए प्राकृतिक घटनाओं में से चार ऐसी घटनाएं हैं जो किसी न किसी जल विद्युत परियोजना के पास घटी हैं
- इसके साथ ही अगर पिछले 1 वर्ष के प्राकृतिक घटनाओं को दिखा जाते तो ये किसी पावर प्रोजेक्ट या नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के आस पास घटती हुई।
- जिस कारण इन परियोजनाओं को लेकर सवाल उठते हैं।
- इन घटनाओं में जान और माल दोनों की हानि होती है
- कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है की इस प्रदेश में हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बनने से यहां पारिस्थितिकी में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।



## 2024 की आपदाएं :-

- हिमाचल प्रदेश में 7 स्थानों में बाढ़ फटने की घटनाएं 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हुईं।
- इसमें से 4 ऐसे स्थान पर पावर प्रोजेक्ट्स मौजूद थे।
- मनाली के धुंधी में 25 जुलाई को अंजनी महादेव नाले में बाढ़ फटने से बाढ़ आ गई जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया।
- यहीं पर 9 मेगावाट को पावर प्रोजेक्ट भी है।





- हिमाचल में एक साथ 31 जुलाई की रात चार स्थानों में बादल फटे । इनमे से एक स्थान मलाणा पावर प्रोजेक्ट भी था जिसके स्टेज 1 के पास डैम में बाढ़ आ गई और डैम फटने से निचले क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ।

### **क्यों आ रही है इतनी प्राकृतिक आपदाएं:-**

- 1.इस राज्य में विद्युत परियोजना के लिए काफी डैम बनते हैं जिससे पानी के भीतर मलवे का जमाव होता है इसमें लकड़ी और अन्य ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं
- जो धीरे-धीरे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ते लगते हैं और मिथेन गैस की उत्पत्ति का कारण बनते हैं,



- यही मिथेन गैस यहां के तापमान को सामान्य के मुकाबले अधिक बढ़ा देती है।
- इस कारण ही इन परियोजना क्षेत्रों में अधिक बाढ़ल फटने और लैंड स्लाइड जैसी आपदाएं बार बार हो रही हैं।
- 2. हिमाचल के जो पहाड़ हैं बह समय के साथ और अवैज्ञानिक परियोजनाओं के कारण कमजोर पड़ गए हैं जिनमें मानवीय दखल जैसे की कटान, मिट्टी की डंपिंग जैसे कारणों से लैंडस्लाइड की घटनाएं अधिक बढ़ गई हैं।



## हिमाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं :-

- राज्य में 174 कुल परियोजनाएं हैं जिनमें छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।
- इन परियोजनाओं में 11209 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है।
- राज्य में कुल 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है इसमें राज्य सरकार और वृद्धि करना चाहती है।



## राज्य में प्राकृतिक आपदाएं और उससे होने वाले नुकसान

- **वर्ष 2021 में :-** प्राकृतिक आपदाओं से :- जिसमें 476 जानें गईं और 1151 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था।
- **वर्ष 2022 में प्राकृतिक आपदाओं से :-** 276 जानें गईं, 939 करोड़ का नुकसान और
- **वर्ष 2023 में :-** प्राकृतिक आपदाओं से :- 441 जानें गईं 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान और थी।
- **वर्ष 2024 में अभी तक :-** प्राकृतिक आपदाओं से :- 73 लोगों की जान गई जबकि 648 करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान हुआ।



### प्रश्न 3 : निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. भारत में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता पवन ऊर्जा से अधिक है।
- 2. जल विद्युत उत्पादन की प्रमुख एजेंसी NHPC (National Hydroelectric Power Corporation) है।
- 3. भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी है।

### सही विकल्प चुनें:

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



## व्याख्या:

- भारत में जल विद्युत की कुल स्थापित क्षमता पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक रही है।
- NHPC भारत में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और संचालन की प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भाखड़ा नांगल (1325 मेगावाट) है, जबकि टिहरी (1000 मेगावाट) सबसे बड़ी में से एक है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है।